हिन्दी पाक्षिक

# महानगर स्तंभ

RNI NO. RAJHIN/2017/70561

❐ वर्ष-9 ❐ अंक-1 जयपुर, बुधवार 1 जनवरी, 2025 ❐ एक प्रति 5 रुपये ❐ कुल पृष्ठ-4

## सम्पादक की कलम से...

नया साल 2025 के शुभारंभ पर सभी पाठकों को हार्दिक बधाई। 2025 के प्रारंभ होने के साथ ही हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र महानगर स्तंभ ने अपने नवम वर्ष में प्रवेश किया। महानगर स्तंभ की षुरूआत आठ साल पहले 01 जनवरी 2017 को हुई थी। पहले अंक से ही समाचार पत्र के साथ सभी प्रबुद्धजन पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं का साथ मिला और सीधी के सहयोग के कारण ही महानगर स्तंभ लगातार आगे बढ़ता रहा। पहले अंक से लेकर आज तक हमेषा ही पाठकों ने महानगर स्तंभ के प्रति अपनापन बनाए रखा। समाचार पत्र ने हमेषा सभी की उम्मीदों के अनुसार ही कार्य किया गया। समाचार पत्र के साथ जुड़े सभी पाठकों, चिंतकों तथा बुजुर्गों के साथ, मार्गदर्शन, स्नेह और अपनेपन ने समाचार पत्र को विषिष्ट बनाया। बीते सात सालों के दौरान समाचार पत्र द्वारा हमेषा ही विभिन्न अवसरों एवं त्यौंहारों तथा आयोजनों पर विविध सामग्री, आलेख तथा विषेषांक प्रकाषित किए। पाठकों के आलेख एवं कविताएं, विचार भी प्रकाषित किए। पाठकों के लिए समाचार पत्र हमेषा ही उपयोगी एवं रूचिपूर्ण रहा। पाठकों के सुझावों एवं मार्गदर्षन के कारण समाचार पत्र पाठकों को हमेशा रूचिकर अखबार प्रदान कर अपनी विषिष्ट जगह बनाए रखने में सफल रहा। कोरोनाकाल जैसे मुष्किल दौर में भी पाठकों का लगातार स्नेह समाचार पत्र को मिलता रहा। इसके लिए समस्त पाठकों समाचार पर साधुवाद करता है। अनवरत सफलतापूर्वक सात आठ साल पूरे होने पर महानगर स्तंभ हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र अपने सभी पाठकों, विज्ञापनदाताओं तथा शुभचिंतकों के असीम प्यार, सहयोग और अपनेपन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। महानगर स्तंभ समाचार पत्र के प्रति सभी का जुड़ाव इसी तरह लगातार बना रहे।

## लघु उद्योग भारती के अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र का उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अपरैल पार्क औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती द्वारा निर्मित सोहनसिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 11 दिसम्बर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उनके साथ डॉ.कृष्ण गोपाल, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मौजूद थे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किसी आकस्मिक दुर्घटना घटित होने के कारण शामिल होना संभव नहीं हो पाया था। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह उपस्थित रहे।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव नरेश पारीक ने सेवा सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह कौशल केंद्र राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय कौशल प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे वे औद्योगिक संस्थानों में कुशल कार्मिक के रूप में अपनी सेवाएँ दे सकें। यह केंद्र लघु उद्योग भारती के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जिसकी स्थापना संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र जी के नेतृत्व में हुई है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और कौशल केन्द्र के समन्वयक महेन्द्र खुराना के अनुसार केंद्र में विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है जैसे उद्यमिता विकास, फैशन और परिधान, ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई, कशीदाकारी, खाता और वित्त प्रबंधन, जीएसटी, एमएस वर्ड, आईटी उपकरण, इन्क्यूबेशन स्टार्टअप, विद्युत वाहन मरम्मत, ड्रोन संचालन, थ्रीडी प्रिंटिंग, सौर उपकरण निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हस्तशिल्प, टेराकोटा, ब्लू पोटरी, और वुड कारविंग आदि। 4015 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित यह केंद्र राज्य का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र है।

## भारत की हरित बहाली: पर्यावरण संरक्षण दिशा में महत्वपूर्ण अध्याय

वन कार्बन को अवशोषित करके, जैव विविधता को संरक्षित करके और स्वच्छ हवा और पानी प्रदान करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, बढ़ते पर्यावरणीय दबाव इन आवश्यक पारिस्थितिकी प्रणालियों को चुनौती दे रहे हैं। यद्यपि, भारत में एक सकारात्मक बदलाव हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में दर्शाया गया है कि देश का वन और वृक्ष क्षेत्र अब 827,357 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का 25.17 प्रतिषत है। इसमें 715,343 वर्ग किलोमीटर (21.76 प्रतिषत) वन क्षेत्र और 112,014 वर्ग किलोमीटर (3.41 प्रतिषत) वृक्ष क्षेत्र शामिल हैं। यह प्रगति पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने के भारत के सफल प्रयासों को दर्शाती है।

### आईएसएफआर 2023- भारत के वनों की एक झलक

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023, उपग्रह डेटा और क्षेत्र की जानकारी का उपयोग करके देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन है। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी, और आईएसएफआर 2023 इसका 18वां संस्करण है। रिपोर्ट दो खंडों में प्रकाशित की गई है। खंड-एक में राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आच्छादित वन क्षेत्र, मैंग्रोव आच्छादित क्षेत्र, वन में लगने वाली आग, बढ़ती हुई वन संपदा, कार्बन स्टॉक, कृषि वानिकी, वन विशेषताएं और दशकीय परिवर्तन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। खंड-दो में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वन आच्छादित क्षेत्र और क्षेत्र सूची डेटा पर विस्तृत जानकारी दी गई है जिसमें जिला और वन प्रभाग के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र डेटा भी शामिल है।

### वन क्षेत्र में वृद्धि

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 भारत के वन क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि पर प्रकाश डालती है जो 2013 में 698,712 वर्ग किमी से बढ़कर 2023 में 715,343 वर्ग किमी हो गया है। आग की घटनाओं में भी कमी आई है, 2023-24 में 203,544 आग के हॉटस्पॉट दर्ज किए गए जो 2021-22 में 223,333 से कम है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य के अनुरूप देश ने 30.43 बिलियन टन सीओ2 समकक्ष का कार्बन सिंक हासिल किया है। यह 2005 से वन और वृक्ष आच्छादन में अतिरिक्त 2.29 बिलियन टन

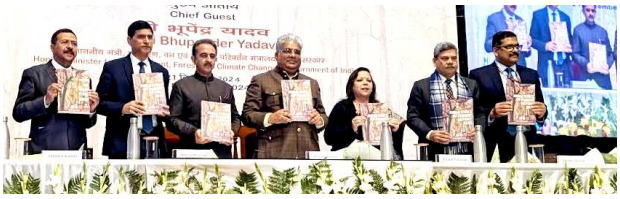


कार्बन सिंक को दर्शाता है, जो 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन सीओ2 समकक्ष के लक्ष्य के करीब है।

### वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएं और पहल

भारतीय वन सर्वेक्षण ने वन क्षेत्र का बेहतर मानचित्र प्रस्तुत करना, एक उन्नत वन अग्नि चेतावनी प्रणाली के निर्माण और राष्ट्रीय वन सूची के पहले पांच वर्षीय चक्र को पूरा करने के माध्यम से वन निगरानी में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसने वन विकास और कार्बन स्टॉक पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन सीमाओं के डिजिटलीकरण ने वन क्षेत्र के आकलन में काफी सुधार किया है। इन पहलों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन और वृक्ष क्षेत्र का विस्तार करने और मैंग्रोव और आर्द्रभूमि के संरक्षण के प्रयासों के साथ मिलकर वन क्षेत्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। यहाँ कुछ योजनाएँ दी गई हैं जिन्होंने इन प्रगति का समर्थन किया है-

- हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम) - फरवरी 2014 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से संरक्षण, बहाली और विस्तार पहल के माध्यम से भारत के वन क्षेत्र को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम ने 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी बहाली प्रयासों के लिए 944.48 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

नगर वन योजना (एनवीवाई) - 2020 में स्थापित, यह योजना शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान विकसित करने पर केंद्रित है। मंत्रालय ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 546 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसके लिए 431.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई) - पौधों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना पूरे भारत में स्कूलों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करती है। 4.80 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 743 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल - इस पांच वर्षीय पहल (2023-2028) का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को बहाल करना और बढ़ावा देना है, जिससे तटीय आवासों की स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जैसे राज्यों को 17.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत, मैंग्रोव और कोरल रीफ के संरक्षण और प्रबंधन घटक के माध्यम से मंत्रालय ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मैंग्रोव की संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह पहल 9 तटीय राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश तक फैली हुई है, जिसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा करना है।

- जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना- यह योजना देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण पर आधारित है।
- एक पेड़ माँ के नाम - प्रधानमंत्री ने 5 जून 2024 को इसका शुभारंभ किया था। यह अभियान नागरिकों को माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे प्रकृति और पोषण के बीच गहरा संबंध बढ़ता है।

प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) - यह योजना वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के अनुरूप, गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के कारण वन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई करती है।

- बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनरोपण लक्ष्य - मंत्रालय केन्द्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं तथा गैर सरकारी संगठनों, निजी संगठनों और नागरिक समाज के प्रयासों का मिश्रण उपयोग करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक वनरोपण लक्ष्य निर्धारित करता है।
- जागरूकता और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान - मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव और वन्यजीव सप्ताह जैसे कार्यक्रमों के साथ-साथ सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सूचनात्मक अभियानों के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है।
- भारतीय वन प्रबंधन मानक, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता - 2023 का एक हिस्सा। यह मानक टिकाऊ वन प्रबंधन की निगरानी के लिए मानदंड और रूपरेखा स्थापित करता है और भारतीय वन तथा लकड़ी प्रमाणन योजना का समर्थन करता है जिससे विशेष रूप से छोटे पैमाने के लकड़ी उत्पादकों को लाभ मिलता है।
- वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना-2018 - यह योजना वन में लगने वाली आग को रोकने लचीलापन बनाने और अग्नि नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामुदायिक क्षमता बढ़ाने के उपाय प्रदान करती है।

संयुक्त वन प्रबंधन और पारिस्थितिकी विकास समितियां - राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप मंत्रालय ने बेहतर वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है जिससे प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों और न्यायालय के आदेशों के सख्त पालन के माध्यम से वनों, मैंग्रोव और आर्द्रभूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

### वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा

भारत में वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन एक मजबूत कानूनी ढांचे द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। प्रमुख कानूनों में भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 शामिल हैं जिनका उद्देश्य वन्यजीव प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना है जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण भी शामिल है।

## संपादकीय

# 2024 में भारतीय विदेश नीति

2024 में वैश्विक परिदृश्य अत्यधिक जटिल और अस्थिर है। यूरोप और मध्य पूर्व में दो महत्वपूर्ण युद्धों ने न केवल भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है अपितु वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा को भी अस्थिर कर दिया है। इन संकटों ने अन्य क्षेत्रों में चुनौतियों को बढ़ा दिया है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर और भारत समेत इसकी सीमाओं पर चीन की बढ़ती आक्रामकता ने क्षेत्र में अस्थिरता का वातावरण बना रखा है। म्यांमार के आंतरिक संकट का इस क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा है और बांग्लादेश को अत्यधिक राजनीतिक अशांति का सामना करना पड़ा है, जिसने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और अल्पसंख्यक समुदायों पर इसके प्रभाव और क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। भू-आर्थिक चुनौतियों में वृद्धि हुई है। वैश्विक मुद्रास्फीति अधिक बनी हुई है, महामारी और यूक्रेन युद्ध से बाधित आपूर्ति श्रृंखलाएं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बढ़ते कर्ज से जूझ रही हैं। चीन की आर्थिक मंदी ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है, इसके व्यापक प्रभाव वैश्विक व्यापार में महसूस किए जा रहे हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान का आर्थिक संकट गंभीर बना हुआ है, जबकि श्रीलंका और मालदीव हाल की वित्तीय उथल-पुथल से उबर रहे हैं, भारत उनकी स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन परस्पर जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए कूटनीति और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। भारत ने ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उल्लेखनीय कुशलता और दक्षता का प्रदर्शन किया है। इन अशांत स्थितियों के बीच भारत ने न केवल रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ अपना रास्ता तय किया है, बल्कि विश्व मंच पर एक विश्वसनीय भागीदार और स्थिरता में सहायक शक्ति के रूप में भी उभरा है।2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय कूटनीति ने भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है।

# सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला में राज्यपाल ने की शिरकत

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे 30 दिसम्बर को जवाहर कला केंद्र में आयोजित सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2024 में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान वहां देशभर से आए महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम उदाहरण है। राज्यपाल बागडे ने मेले में लगे विभिन्न राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद स्टॉल का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरह के मेलों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिला समूहों के उत्पादों को बड़े स्तर पर बाजार मिलता है। उन्होंने वहां प्रदर्शित भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प, कारीगरी, वस्त्र उत्पादों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। राज्यपाल को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के भास्कर सांवत ने उनकी अगवानी की। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने विभिन्न स्टॉल और उत्पादों के बारे में बताया।

# राजस्थान युवा महोत्सवः 8 से 12 जनवरी तक होगा युवा महोत्सव का आयोजन

जयपुर। राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से 12 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के संबंध में 30 दिसम्बर को युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के. पवन की अध्यक्षता में एसएमएस स्टेडियम के मीटिंग हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पवन ने बताया कि यह चार दिवसीय महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित होगा। इसका आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 50 हजार, द्वितीय स्थान पर 25 हजार और तृतीय स्थान पर 10 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों एवं योजनाओं की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस संबंध में संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। चार दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा तथा आमजन भी इस महोत्सव के प्रत्यक्ष साक्षी होंगे।

**यूथ आइकॉन अवॉर्ड**

युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान और तकनीकी, नवाचार, साहसिक कार्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। चयनित युवाओं को एक लाख रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। नीरज के. पवन ने यह भी बताया कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और यूथ आइकॉन अवार्ड में चयनित प्रतिभागियों को 12 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही, युवा दिवस पर आयोजित 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2025 में भाग लेने के लिए राजस्थान दल को 9 जनवरी को नई दिल्ली रवाना किया जाएगा।

**राजस्थानी संस्कृति की झलक**

युवा मामले एवं खेल विभाग की उप शासन सचिव अनीता मीणा ने बताया कि महोत्सव में राजस्थानी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ एनसीसी, पुलिस और विभिन्न संस्थानों द्वारा बैंड प्रदर्शन भी किया जाएगा। बैठक में युवा बोर्ड के सदस्य सचिव कैलाश चंद पहाड़िया और सूचना एवं जनसंपर्क, पर्यटन, शिक्षा, डीओआईटी, स्काउट गाइड, कौशल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

# सिविल डिफेंस के जवानों ने आपदा नियंत्रण में निभाई अहम जिम्मेदारी

जयपुर। जयपुर जिले में नागरिक सुरक्षा के साहसिक एवं समर्पित जवान आपदा प्रबंधन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अपनी जान की परवाह किये बगैर सिविल डिफेंस के जांबाज जवान जिला कलक्टर के निर्देशन एवं उप नियंत्रक अमित शर्मा के नेतृत्व में बेमिसाल कार्य कर रहे हैं। 29 दिसम्बर को सुबह करीब 8 बजे विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 14 स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना नियंत्रण कक्ष में प्राप्त हुई। सूचना मिलने के पश्चात उप नियंत्रक अमित शर्मा के नेतृत्व में सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम मौके के लिए तत्काल रवाना हुई एवं नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के वाहनों को भी मौके पर रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी फैक्ट्री का सर्च किया। इसके अतिरिक्त फायर कर्मियों का फायर फाइटिंग करने में सहयोग किया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया।

इससे पूर्व 28 दिसम्बर की रात को करीब 10 बजे नियंत्रण कक्ष को टाटियावास टोल के पास सीकर रोड पर एक सीएनजी का टैंकर पलटने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके बाद सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे और टोरेंट गैस कंपनी की टेक्निकल टीम से समन्वय स्थापित करते हुए मौजूद गैस के प्रेशर को डॉउन करवाया। रेस्क्यू कार्य के दौरान जयपुर सीकर हाईवे को दोनों साइड से वाहनों की आवाजाही को बंद किया गया एवं बड़ी दुर्घटना पर समय रहते काबू पा लिया। ऑपरेशन पूरा होने के पश्चात हाईवे को आवागमन के लिए खोल दिया गया।


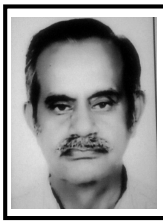

सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

बृज मोहन मदान

(एडवोकेट) राज. उच्च न्यायालय

मो: 93513-60578

सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

राजेश गुप्ता

(एडवोकेट) राज. उच्च न्यायालय

मो: 9309212401

सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy New Year 2025 राजेन्द्र माहेश्वरी Happy New Year 2025


# प्रतापगढ़ कलेक्टर ने रेडियो पर करा विलक्षण प्रतिभा सुशीला मीणा से संवाद

प्रतापगढ़/जयपुर। प्रतापगढ़ जिले की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ के रेडियो पर प्रत्येक रविवार को हौसलों की उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया जिले की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं से संवाद करते है ताकि उनकी प्रेरक कहानियों से जिलेवासियों को प्रोत्साहन मिल सके। इसे जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है। इसी कड़ी में जिला कलक्टर ने प्रतापगढ़ जिले की नन्ही प्रतिभा सुशीला मीणा से संवाद किया। हाल ही में सोशल मीडिया पर सुशीला का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था। लोगों ने उनकी गेंदबाजी को काफी सराहा। उनके वीडियो को क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जहीर खान जैसे महान क्रिकेटरों ने भी साझा किया, जिससे सुशीला की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और जिले का नाम रोशन हुआ।

कार्यक्रम में सुशीला ने बताया कि वह हर रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करती हैं और पढ़ाई भी करती हैं, जिसमें गणित उनका पसंदीदा विषय है। सुशीला की इच्छा है कि उनके गांव के बच्चों को भी खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहती हैं कि उनके साथ की लड़कियां भी आगे बढ़ें । इसके अलावा जिला कलेक्टर ने सुशीला के पिता से भी बातचीत की, जिन्होंने कहा कि उनका हमेशा से यही मानना है कि बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें खेलों में भाग लेने का पूरा अवसर देना चाहिए। उन्होंने कभी अपने बच्चों को खेल से रोका नहीं और हमेशा उनका उत्साहवर्धन किया। हौसलों की उड़ान कार्यक्रम का उद्देश्य जिले की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी सफलता की कहानी से अन्य लोगों को प्रेरित कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि अधिक से अधिक युवा अपनी प्रतिभा को पहचानें और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहें।

# न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने 30 दिसम्बर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी ने सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। यह कार्यभार उनके और पिछले सप्ताह आयोग में सदस्य के रूप में शामिल हुए प्रियांक कानूनगो के स्वागत के लिए आयोजित एक समारोह में संभाला गया। उन्हें माननीया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 21 दिसंबर 2024 को नियुक्त किया था। इस अवसर पर आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी, महासचिव भरत लाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने मानवाधिकारों को महत्व देने और उनका पालन करने की भारत की प्राचीन परंपरा पर प्रकाश डाला, इससे पहले भी इस अवधारणा को वैश्विक मान्यता मिली थी। तमिल कवि थिरुवल्लुवर का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकार भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने में गहराई से अंतर्निहित हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग आधारित प्रयास की आवश्यकता है।





तमिलनाडु के मन्नारगुडी में 30 जून, 1958 को जन्मे न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने चेन्नई के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज से रसायन विज्ञान में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और बाद में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। उन्हें 16 फरवरी, 1983 को बार के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया और उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में 23 वर्षों तक वकालत की। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने 2006 में मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और 2009 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उन्हें 2016 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और विभाजन के बाद, उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय में अपना कार्यकाल जारी रखा। 2019 में उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उसी वर्ष बाद में वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए। 2016 की विमुद्रीकरण नीति और रिश्वतखोरी के मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की वैधता से जुड़े मामलों जैसे ऐतिहासिक मामलों सहित 102 फैसले लिखने के बाद वे 29 जून, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए।

मध्य प्रदेश के विदिशा के मूल निवासी प्रियांक कानूनगो ने माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी की डिग्री प्राप्त की है और वे भारत में बाल अधिकारों और शिक्षा के लिए समर्पित वकील रहे हैं। उन्होंने 2018 से 2024 तक दो कार्यकालों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान, कानूनगो ने भारत के अद्वितीय सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप बाल कल्याण प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया, विदेशी मॉडलों को अपनाने के बजाय भारतीय समस्याओं के लिए भारतीय समाधान की वकालत की। उन्होंने पिंजरा-द केज नामक पुस्तक लिखी है, जो बच्चों की देखभाल से जुड़े संस्थानों में उनके जीवन का व्यापक रूप से पता लगाती है। उनके नेतृत्व में, एनसीपीसीआर ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई पहल कीं, जिसमें बच्चों को अनुचित सामग्री से बचाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित करना शामिल है। उन्होंने हितधारकों की सहभागिता को बेहतर बनाने के लिए कई पोर्टल भी पेश किए और अपने कार्यकाल के दौरान 100,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया।

न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी का जन्म 20 जुलाई, 1962 को ओडिशा के नयागढ़ जिले में हुआ था। वे एक प्रख्यात विधिवेत्ता हैं, जिन्हें भारतीय कानून में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कटक के एमएस लॉ कॉलेज से एलएलबी और एलएलएम की डिग्री प्राप्त की है तथा संबलपुर विश्वविद्यालय से कानून में पीएचडी की है। डॉ. सारंगी ने 1985 में अपना कानूनी करियर शुरू किया, तथा 27 वर्षों से अधिक समय तक सिविल, आपराधिक, संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में वकालत की। उन्हें उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए 2002 में स्वर्ण पदक के साथ प्रतिष्ठित हरिचरण मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 जून 2013 को उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 152,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया और लगभग 1,500 निर्णय लिखे। जुलाई 2024 में, वे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति सारंगी ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और किशोर न्याय समिति सहित विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक समितियों में योगदान दिया है, और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैधानिक संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं।

घनश्याम विजयवर्गीय
(एडवोकेट) राज. उच्च न्यायालय
मो: 9352739871, 8764328592
सभी देशवासियों को नववर्ष की मंगलकामनाओं सहित हार्दिक शुभकामनाएं


प्रो. बंटी गुप्ता
सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
गुप्ता ट्रेंडर्स
प्लास्टिक, कटलरी एवं हॉजरी में हजारों आईट्मों के होलसेल विक्रेता
शॉप नं. 2175, पहले चौराहे से पहले, राजाशिवदास जी का रास्ता
चौगान स्टेडियम के सामने, गणगौरी बाजार, जयपुर

सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

पंकज गुप्ता (चेयरमैन)
फ्लेम्स इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
मो: 9413344446


सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय कुमार जैन
(समाजसेवी) कालाडेरा वाले
मो: 9351055600

सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

चन्द्र प्रकाश खेतानी
(एडवोकेट)
राज. उच्च न्यायालय
मो: 99283-35592
93145-05592

क्रिएटिव स्टडी प्वाईंट की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
Creative Study Point
CSP Since 2006
नींव से निर्माण तक
Batches Start
CREATIVE STUDY POINT
11th & 12th (Physics, Chemistry, Bio & Maths)
11th & 12th (Commerce)
Separate Batches For Both Medium
9th & 10th (Science, Maths, English, S.St)
B.Sc (Maths & Physics)
Mob. 9414795238
9829033204
Add. P.No. 10, Krishna Colony, Near Modal School, Ramgarh Mode, Jaipur

सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

दौलत त्रिलोकानी
(अध्यक्ष)
युवा जागृति संगठन
मो: 9982944038

सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं
SHAH EDUCOM
A UNIT OF RIGHT VISION COMPUTER INSTITUTE
SYNONYM OF QUALITY EDUCATION
222, RAY COLONY, HASANPURA-C, KHATIPURA ROAD, JAIPUR
Ph. 2221152 • Mob. : 9024450092, 7791944837 Email : shaheducomitgk@gmail.com
COMPUTER COURSE: BASIC • TALLY, DTP • C, C++, JAVA
COACHING CLASSES: 1 to 10th MATHS & SCIENCE
COMMERCE CALSSES: 11TH & 12TH, B. COM, BBA, BCA
TYPING CLASSES: HINDI / ENGLISH (COMPUTER & TYPEWRITER), TYPING BY SOFTWARE, TYPING CLASSES FOR COMPETITION EXAM
RS-CIT
CCC
O-LEVEL
WI-FI CAMPUS
Teach By Best Faculty

सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

श्याम प्रकाश शर्मा
(एडवोकेट)
राज. उच्च न्यायालय
मो: 9414077369

# iTVoice® all things tech.

## India's Premier IT Magazine & First Daily Tech News OTT

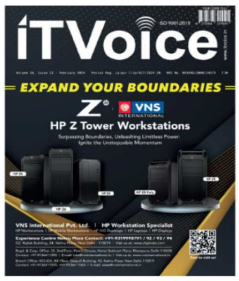


Magazines & Newspapers

iV

Highest Digital Presence

www.itvoice.in

Daily Tech News & Podcasts

Contact for Print & Digital Marketing

+91 141 4014911
info@itvoice.in

ICPL
www.icpljpr.com

Professional IT Support

Domain & Hosting
Web Development
Customized Software Solution
Web Operation
Client / Server Management
Network Maintenance
Service Desk Support
Customized IT Support Services
Dealing in all Major Brands

Informatic Computech Private Limited

Jaipur - Rajasthan (Ph.) +91-141-2280510 md@icpljpr.com


स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक तरूण कुमार टांक के लिये महारानी प्रिन्टर्स प्लाट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 52/121, वीरतेजाजी रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। सम्पादक-तरूण कुमार टांक Email: mahanagarstambh@gmail.com